from time to time at Central and State levels and necessary steps|initiatives are taken to improve the lot of rural women. During 1993-94, the coverage of women beneficiaries under IRDP was 33.64 per cent under IRY women had a share of 25.06 per cent in the total employment generated. The programme of DWCRA has also benefited the rural women in making them self confident and improved their social and economic status.

Development of Wasteland in Bihar

.. 506. SHRI JANARDAN YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how much wasteland was put to agricultural and horticultural use in Bihar during the last four years;

(b) how much total wasteland was there in Bihar four years ago and how much is there now;

(c) how much money was given to the State Government during this Period; and

(d) what steps are being taken to develop the wastelands?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Irrigations / Building Schemes to provide drinking water to Maharashtra

507. SHRI SATISH PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have appro ved irrigation of bunding schemes to pro vide drinkiig water to Maharashtra; if so, the details of location;

(b) what are the scheme that remain incomplete despite approval due to objec tions from forest and environmental dep artments; and

(c) whether Government would consider introdirring package deal inclusive of approvals from all Government Depart-ments prior to sanction of the Scnemos?

THE MINISTER OF STATE IN IME MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAM-BHAI PATEL); (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not ariac.

पेयजल के एक स्रोत के संबंध में सर्वेक्षण

508. श्री सुरेश पचौरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ वर्षों के बाद देश के प्रत्येक गांव और बासस्थल में पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने का केन्द्रीभूत कार्य आरंभ हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस आश्चर्य को अंजाम देने के लिये 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि लगाई गई थी ;

(ग) क्या 1986 के मुकाबले ऐसे बासस्थलों की संख्या अधिक है जहां शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या 1985 के सर्वेक्षण से यह पता चला कि 1.62 लाख गांवों में पेयजल का मात्र एक स्रोत है ;

(ङ) क्या सरकार ने जल संबंधी अपने विभिन्न मिशनों में सर्वप्रथम प्रौद्यो-गिकी मिशन को आरंभ किया ;

(च) यदि हां, तो क्या यह मिशन का काम 1991 में पूरा हो जाना था लेकिन अभी भी 2,365 समस्याग्रस्त गांव है ;

(छ) क्या सरकार ने 1991 में एक और सर्वेक्षण के लिये कहा था जो अक्तूबर, 1993 में पूरा हो गया और जिसे यह पता चला कि 60,000 गांव जल स्रोत रहित है और 1.20 लाख वास स्थल जल रहित है ;

(ज) क्या इस सर्वेक्षण के अनुसार 1986 के मुकाबले जब यह मिशन शुरू हुआ था, 20,000 और ऐसे वास स्थल है जहां जल का कोई स्रोत नहीं है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभ ई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बिना सुरक्षित पेयजल वाली बसावटों के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां। लेकिन 1.4.92 को 2243 समस्याग्रस्त गांव थे।

(छ) बसावटों के सर्वेक्षण 1991–93 द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों का वैद्धीकरण पूरा नहीं किया गया है।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण सफाई योजना का कार्यान्वयन

509. श्री राम लेउमनानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मई, 1994 के "डेली टैलीग्राफ" में "रूरल सेनीटेशन स्कीम ए फेलियर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन गत वर्षों के दौरान इन प्रयोजनों हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993 94 के लिये क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और वास्तव में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जा सके ;

(घ) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी तथा उनके संबंध में रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी एक ही होने के कारण, संबंधित मुद्दों के आवश्यक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कोई विशेष तंत्र स्थापित करेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान कम लागत वाले